



डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ गैर कानूनी घोषित

अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया

वॉशिंगटन डीसी, 20 फरवरी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप द्वारा लगाए गए बड़े पैमाने पर टैरिफ (आयात शुल्क) गैरकानूनी हैं।

कोर्ट ने कहा कि ट्रंप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईपीए) का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति के रूप में असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं रखते।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखी कि यह कानून आपात स्थिति के लिए है, न कि टैरिफ लगाने के लिए। यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीति को गहरा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उन्होंने कई देशों पर आपातकाल के नाम पर भारी टैरिफ थोपे थे।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति असीमित और एकतरफा टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने के लिए साफ तौर पर संसदीय अनुमति

जरूरी है। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की विदेश नीति और आर्थिक एजेंडे पर सीधा वार है।

गौरतलब है कि पिछले साल इसी कंजरवेटिव झुकाव वाली अदालत ने इमिग्रेशन, एजेंसी हैड्स की बर्खास्तगी और सरकारी खर्च में कटौती जैसे मामलों में ट्रंप का साथ दिया था। ऐसे में यह फैसला और भी अहम माना जा रहा है।

ट्रंप ने 12 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी कि अगर कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कंपनियों और देशों के निवेश दावों को जोड़ दिया जाए तो बोझ खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है।

डॉनल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बीते साल अगस्त में एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप के कदम को गैरकानूनी करार दे दिया था, लेकिन अदालत ने टैरिफ को लागू रहने

- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा भारी झटका दिया और कहा कि ट्रंप को इन्टरनैशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि यह कानून आपात स्थिति के लिए है, न कि टैरिफ लगाने के लिए।
- चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति एकतरफा टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा करते हैं, पर, इसके लिए संसदीय अनुमति की जरूरत है।
- सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि उन्होंने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं।
- ट्रंप ने इस मसले पर जनवरी में कहा भी था, अगर कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं।
- हालांकि कोर्ट के आदेश से सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर अलग कानूनों के तहत टैरिफ लगाए गए थे, जो अभी कायम रहेंगे, लेकिन रैसिप्रोकल टैरिफ, दंडात्मक टैरिफ खत्म कर दिए गए हैं।

दिया था। इसके बाद वाइट हाउस की ओर से अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन को झटका देने दिए हुए टैरिफ को गलत बताया है।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया था कि अगर केस हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट ने ट्रंप के वकीलों की दलील को नहीं माना और टैरिफ रद्द

करने का फैसला सुनाया। यह मामला डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे का पहला बड़ा मुद्दा है, जो सीधे सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है।

कोर्ट के आदेश से ट्रम्प के सभी

इस फैसले से भारत पर तुरंत क्या असर होगा

जयपुर, (का.सं.), 20 फरवरी। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द करने के फैसले का मतलब है कि भारत से अमेरिका को होने वाले 55 प्रतिशत निर्यात पर 18 प्रतिशत का पारस्परिक टैरिफ नहीं लगेगा।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार,

अमेरिका की सर्वोच्च अदालत के फैसले से भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। जीटीआरआई के विश्लेषण के अनुसार, "पारस्परिक टैरिफ को हटाने से अमेरिका को होने वाले भारत के लगभग 55 प्रतिश निर्यात 18 प्रतिशत शुल्क से मुक्त हो जाएंगे, और उन पर केवल मानक

एमएफएन टैरिफ ही लागू होंगे।" थिंक टैंक के अनुसार, कुछ पेचिदगियां मौजूद हैं। इस वजह से इस्पात और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत और कुछ ऑटो घटकों पर 25 प्रतिशत रहेगी। निर्यात मूल्य के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से वाले उत्पाद, जिनमें स्मार्टफोन, पेट्रोलियम उत्पाद और दवाइयां आदि अमेरिकी टैरिफ से मुक्त रहेंगे।

‘मेरे नाम से ही आए दिन नई साइट बन जाती हैं, मेरे फोटो अपलोड हो जाते हैं

जयपुर आए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा

जयपुर, 20 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि उनके नाम से आए दिन नई साइट बन जाती हैं और उसमें मेरे फोटो अपलोड हो जाते हैं। इसी तरह की साइट से मेरी बेटी और बहन को मैसेज भेजे गए, लेकिन वो उनकी भाषा समझ गई। जब मैंने इसकी शिकायत साइबर पुलिस में की तो पता चला कि ये सभी साइट्स नाइजीरिया में बन रही हैं।

सीजेआई ने यह विचार शुरुवार को आरआईसी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर सुरक्षा विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि पहले सोचो, फिर बोलो, पहले विचार करो, फिर काम करो। डिजिटल अपराध

- जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर सुरक्षा विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया और कहा, साइबर फ्राँड से 50,000 करोड़ रुपए तक ठगे गए हैं और करीब 66 लाख शिकायतें लंबित चल रही हैं।

से बचने के लिए हमें इसी को अमल में लाना होगा। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध इस चिंताजनक हालत तक बढ़ गया है कि साइबर फ्राड से पचास हजार करोड़ रुपए ठगे गए हैं और करीब 66 लाख शिकायतें लंबित चल रही हैं। सीजेआई ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए आपसी समन्वय से काम करना होगा। “हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटल तरीके से फ्राँड कर अदालती दस्तावेज तक बन रहे हैं। ऐसे में जल्द ही कि सभी मिलजुलकर इससे लड़ने के लिए खड़े हों।”

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि तकनीक दोधारी तलवार बन चुकी है। एक तरफ डिजिटल तकनीक का अपना फायदा है तो दूसरी तरफ हमें सचेत रहना भी जरूरी है।

साइबर सुरक्षा आज के समय की मांग है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में साइबर स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आज से दस साल पहले पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 फरवरी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने शुक्रवार को राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व

- विनोद जाखड़ को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का करीबी माना जाता है।

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबी विनोद जाखड़ को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया।

यह पहला अवसर है, जब राजस्थान के किसी नेता को इस पद पर नियुक्त किया गया है।

एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, पार्टी निर्वर्तमान अध्यक्ष वरुण चौधरी, जो बिहार से हैं, के योगदान को सराहा करती है।

हिंदुओं के तीन बच्चे होने मुद्दे पर शंकराचार्य ने भागवत का विरोध किया

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, समाज की प्रगति ज्यादा संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति व धार्मिक मूल्यों के आधार पर होती है

- शंकराचार्य ने कहा, ज्यादा बच्चे हों, पर उन्हें संस्कारों व मूल्यों का पाठ ना पढ़ाया जाए तो समाज प्रगति नहीं करता।
- ज्ञातव्य है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हिंदुओं के तीन बच्चे होने ही चाहिए।

को कहा था। पिछले कुछ सप्ताहों में उन्होंने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर तीखे विचार व्यक्त किए हैं, जो प्रायः आरएसएस और भाजपा के प्रति आलोचनात्मक रहे हैं।

इस बार उन्होंने भागवत द्वारा लखनऊ में इस सप्ताह की गई उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने नवविवाहित दंपतियों से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने का आा न किया था। भागवत ने कहा था कि विवाह का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाना और

सामाजिक दायित्व निभाना है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए कहा कि बिना उचित संस्कार दिए केवल अधिक बच्चे पैदा करने से समाज मजबूत नहीं होगा। उन्होंने कहा, “माता-पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ बड़े हों, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म पर अडिगरह सकें। सौ तारे उतनी रोशनी नहीं देते, जितनी एक चाँद देता है।”

शंकराचार्य ने आगे चेतावनी दी कि (हिंदू समाज के भीतर) आंतरिक संघर्ष

उसे कमजोर कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण के वंशजों का उदाहरण दिया, जो बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक कलह से नष्ट हुए थे। “जब संख्या एकता और मूल्यों के बिना बढ़ती है, तो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं।”

दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी भागवत की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है और इसका राजनीतिकरण करने के बजाय, सभी समुदायों को इस पर जिम्मेदारी के साथ, विचार और चर्चा करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी संसाधनों पर दबाव डाल रही है और अनेक परिवार, जिनमें मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं, बढ़ते खर्च और शिक्षा की लागत के कारण कम बच्चे पैदा करने का निर्णय ले रहे हैं।

फिर से राजस्थान हाई कोर्ट को बम की धमकी

जयपुर, 20 फरवरी। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को शुक्रवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई।

- ई-मेल पर भेजी धमकी में सीजेआई का दौरा रह करवाने और 12 बजे तक हाई कोर्ट खाली करने की चेतावनी दी गई थी और कहा था कि कोर्ट में आरडीएक्स लगाया गया है। पर, जाँच व तलाशी में कुछ भी नहीं मिला।

इस बार धमकी भरे मेल में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत के दौरे को रद्द करने की चेतावनी दी गई थी। मेल में लिखा था कि सीजेआई का दौरा कैसिल

रील के प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित की नियुक्ति रद्द करने पर अंतरिम रोक

- केन्द्र सरकार तथा दीक्षित की ओर से अदालत में कहा गया कि “रील मे रीको मात्र 49 फीसदी की निवेशक है, उसका हिस्सा राज्य सरकार का हिस्सा नहीं माना जा सकता। रील के प्रबंध निदेशक की चयन प्रक्रिया में कभी भी राज्य के मुख्य सचिव को पक्षकार नहीं बनाया गया।”
- सुनवाई के दौरान कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा ने भी यह टिप्पणी की कि गाइडलाइन केवल एक दिशा सूचक की तरह कार्य करती है, परंतु वह एक नियम या कानून नहीं है।

कंपनी के अध्यक्ष अथवा एम डी, की नियुक्ति नहीं की जा सकती। वहीं अपीलार्थी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए के शर्मा और सुरुचि कासलीवाल की ओर से कहा गया कि उक्त मामले के संदर्भ में रीको को राज्य सरकार का पक्षकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि रीको एक सरकारी कंपनी अवश्य है और उसके कर्मचारियों, अधिकारियों व प्राइवेट पार्टी किसी संवैधानिक अधिकार की पालना करने हेतु दायर रिट याचिका के मामलों में रीको को सरकार की परिभाषा

में ले सकती है, क्योंकि अंततः ऐसे मामलों में राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को ही अदालत कानून की पालना करने के लिए आदेश दे सकती है, परंतु अन्य व्यवसायिक अनुबंधन के मामलों में रीको एक प्राइवेट कंपनी की भांति ही है, जिसको राज्य सरकार का विभाग नहीं माना जा सकता। इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल व वरिष्ठ अधिवक्ता भरत व्यास ने भी अदालत को यही तर्क

जल महल पर सूर्य किरण और सारंग ने हैरतअंगेज करतबों से किया रोमांचित

आसमान में सधे हुए अंदाज़ में उड़ते हेलिकॉप्टरों ने जटिल संरचनाएँ बनाई और हैरतअंगेज एरियल मूवमेंट्स का प्रदर्शन किया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । जयपुर में शुक्रवार को जल महल पर भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित ब्रांड एंसेसडर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने हैरतअंगेज करतबों से हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उपस्थिति रही। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

जल महल की पाल से खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने पांच रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों के साथ सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। आसमान में सधे हुए अंदाज में उड़ते हेलिकॉप्टरों ने जटिल संरचनाएँ बनाई और हैरतअंगेज एरियल मूवमेंट्स प्रस्तुत कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

हेलिकॉप्टरों की सटीक दूरी, संतुलन और तालमेल भारतीय वायु सेना के अनुशासन एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का जीवंत उदाहरण रहा, जिसकी दर्शकों ने जमकर सराहना की।

इसके पश्चात जब लाल-सफेद रंग के आकर्षक एचएडब्ल्यूके एमके-१32 जेट विमानों ने उड़ान भरी तो वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गुंज उठा। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाईंग तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे



जयपुर में शुक्रवार को जल महल पर भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ।

जटिल और रोमांचक करतबों का प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाश में लहराते तिरंगे रंगों ने दर्शकों के मन में गर्व और देशभक्ति का भाव भर दिया।

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के तीन प्रतिभाशाली पायलट विंग

कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्व्वाइन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही निवासी हैं। अपने गृह नगर में साहस, हुनर और कौशल का प्रदर्शन करना उनके लिए विशेष गौरव का क्षण रहा। दर्शकों ने जांबाज पायलटों के सम्मान में खड़े

होकर तालियों से उनका अभिनंदन किया।

यह आयोजन विशेष रूप से युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरणास्त्रोत बना। कार्यक्रम ने उनमें देशभक्ति, साहस और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह का संचार किया। बड़ी

संख्या में विद्यार्थियों ने इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। रविवार को जल महल पर एरोबैटिक डिस्प्ले का मुख्य एवं विस्तृत आयोजन किया जाएगा, जिसमें और भी भव्य हवाई करतब देखने को मिलेंगे।

181 हैल्पलाइन पर 35 आईएसएस सुनेंगे समस्याएं

जयपुर (कासं)। प्रदेश में आमजन की शिकायतों के समय पर निपटारे को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 35 वरिष्ठ आईएसएस अधिकारियों को राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 पर सीधे ड्यूटी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सचिव से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारी अब सचिवालय स्थित कॉल सेंटर में बैठकर खुद लोगों के फोन उठाएंगे। प्रत्येक अधिकारी प्रतिदिन कम से कम 10 कॉल रिसीव करेगा और समस्याओं का यथासंभव त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन ने आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संपर्क पोर्टल पर दर्ज पुरानी लंबित शिकायतों में से कम से कम 10 मामलों का चयन करें, जिनका समाधान आसानी से संभव है लेकिन वे लंबे समय से अटक हुए हैं। इन मामलों का निस्तारण कर संबंधित व्यक्तियों को जवाब देना अनिवार्य होगा। अक्सर प्रमाण पत्र जारी करने, बिजली-पानी आपूर्ति, सफाई और अन्य बुनियादी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें लंबित रहती हैं, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं भी 181 कॉल सेंटर का दौरा कर रहे हैं और आमजन से सीधे संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रमों में भी शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया जा रहा है।

इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण : मुख्यमंत्री का कांग्रेस का प्रयास निंदनीय’

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के प्रतिष्ठित और गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के आचरण को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी प्रगति, नवाचार क्षमता और उज्ज्वल भविष्य की सराहना कर रहा है, उस समय कांग्रेस द्वारा देश की छवि को धूमिल करने का यह प्रयास निंदनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट

■ कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्रिहत से ऊपर रखा : भजनलाल शर्मा

में विश्वभर से आए विदेशी प्रतिनिधि, निवेशक और दिग्गज तकनीक विशेषज्ञ भारत की बढ़ती वैश्विक साख, डिजिटल क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उभरती नेतृत्वकारी

भूमिका पर सकारात्मक चर्चा कर रहे थे। ऐसे अवसर पर भी कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय मंच से देश की छवि को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का यह रवैया नया नहीं है। कांग्रेस ने व्यापार समझौतों पर भ्रम फैलाने से लेकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और गलतबान में वीरता दिखाने वाले सैनिकों के शौर्य पर प्रश्नचिह्न लगाने तक, अनेक अवसरों पर राष्ट्रिहत से ऊपर अपने राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा

कि आज कांग्रेस ने करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान को चुनौती दी है। भारत की प्रतिष्ठा किसी दल की नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक अस्मिता से जुड़ी है। इसे आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व को बिना विलंब देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जनता कांग्रेस को इस नकारात्मक और अवसरवादी राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

इंटर डिस्क्रॉम तबादलों पर बनेगी उच्च स्तरीय समिति

जयपुर (विसं)। प्रदेश के पावर सेक्टर में इंटर डिस्क्रॉम तबादलों के मुद्दे पर सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित स्थानांतरण संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी।

आमेर मावठे में नौका विहार का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक

20 वर्षों के इंतजार के बाद गुलाबी नगरी में पुनः शुरू हुई व्यवस्था

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । विश्व प्रसिद्ध आमेर महल की तलहटी स्थित मावठा सरोवर में करीब दो दशक बाद फिर से बोटिंग सेवा शुरू की जा रही है। लगभग 20 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यहां ट्रायल संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। जिससे आमेर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। परियोजना प्रभारी सुमित सिंह ने बताया कि 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे से ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल चल रहा रहे पर इसी दिन से आम पर्यटकों के लिए आधिकारिक संचालन आरंभ कर दिया जाएगा। बोटिंग संचालन का अनुबंध पर्यटन विभाग ने जसराज इंग्रू को दिया है। कंपनी ने सरोवर पर दो जेटी स्थापित की हैं।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में 25 पैडल बोट, 5 कश्मीरी शैली की शिकारा, 20 सीटर और 30 सीटर लम्जरी बोट संचालित की जाएंगी। 30 सीटर लम्जरी बोट विशेष आकर्षण रहेगी, जबकि हेरिटेज लुक वाली नावें भी जल्द शामिल की जाएंगी। किराया दरें शीघ्र घोषित की

जाएंगी। वहीं अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षा मानकों, जेटी प्रबंधन और रेस्क्यू सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है। सभी पर्यटकों को लाइफ जैकेट दी जाएगी तथा प्रशिक्षित नाविक, गोताखोर और रेस्क्यू बोट तैनात रहेंगी। हरी-भरी अरावली पहाड़ियों के बीच शांत जल में आमेर महल का प्रतिबिंब और तैरती नावें पर्यटकों को विशेष अनुभव देंगी। पर्यटन विभाग ने कालबेलीया नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और भविष्य में लाइट एंड साउंड शो की भी योजना बनाई है। सरोवर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पर्यटकों के लिए बोटिंग करने का किराया भी जल्द तय किया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइफ जैकेट, प्रशिक्षित नाविक और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही मावठा सरोवर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।



आमेर महल की तलहटी स्थित मावठा सरोवर में करीब दो दशक बाद फिर से बोटिंग सेवा शुरू की जा रही है। लगभग 20 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यहां ट्रायल संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।

आयकर छापेमारी में कान्हा ग्रुप के पास मिली करोड़ों रु. की ज्वैलरी

आयकर टीम को खुफिया स्ट्रॉन्ग रूम मिले जेवरात, एक करोड़ रु. नकद सहित 10 लॉकर चिन्हित

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध फूड चैन कान्हा रेस्टोरेंट समूह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) की कार्रवाई शुक्रवार तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार सुबह शुरू हुई इस समन्वित छापेमारी में जयपुर सहित छह शहरों और मुंबई तक फैले 33 ठिकानों पर सचंच किया जा रहा है। जयपुर में सर्वाधिक 26 परिसरों-कार्यालय, गोदाम और अन्य प्रतिष्ठानों-की जांच चल रही है।

आयकर विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान एक ठिकाने पर दीवार के पीछे बना खुफिया कक्ष मिला। संदेह होने पर दीवार तोड़ी गई तो भीतर मजबूत स्ट्रॉन्ग रूम मिला। जहां से करीब पांच करोड़ रुपये मूल्य की

■ **शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन कान्हा ग्रुप के 33 ठिकानों पर छापेमारी जारी रही**

ज्वैलरी बरामद हुई। सरकारी मूल्यांकनकर्ता आभूषणों का आंकलन कर रहे हैं। अब तक करीब एक करोड़ रुपये नकद भी जब्त किए जा चुके हैं। उससे यह साफ है कि यह टैक्स चोरी का आंकड़ा 100 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा।

इसके अलावा आयकर टीम को 10 बैंक लॉकरों की और जानकारी मिली है, जिन्हें खुलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार

लॉकरों में बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और सोना मिलने की आशंका है। सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग की जांच का दायरा रेस्टोरेंट कारोबार से आगे बढ़कर रियल एस्टेट निवेश तक पहुंच गया है। आमेर स्थित ताज होटल और कूकस के कुंदन वन होटल में निवेश की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। विभाग को संदेह है कि लाघ कम दिखाकर धन को आलीशान संपत्तियों में लगाया गया। आयकर टीमें बैंक खातों, डिजिटल रिकॉर्ड, नकद लेन-देन, प्रॉपर्टी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की गहन जांच कर रही हैं। बड़ी मात्रा में फाइलें व डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए छापेमारी आगे भी जारी रहने की संभावना है।

रैलिंग तोड़कर स्कॉर्पियो में घुसी लोहे की राँड

जयपुर (कासं)। मुरलीपुरा क्षेत्र में शुक्रवार अलसुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बनी लोहे की रैलिंग और जाली तोड़ते हुए उसमें जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोहे का एंगल वाहन का शीशा चीरता हुआ चालक के सीने में जा घंसा।

हैड कांस्टेबल रविंद्र कुमार ने बताया कि हादसे में आनंद सिंह शेखावत (28) निवासी सुंदर विहार कर्धनो की मौत हुई है। वह स्कॉर्पियो चला रहा था। उसके साथ उसका दोस्त शक्ति प्रताप (22) निवासी मुरलीपुरा बैठा था। जो इस हादसे में बाल-बाल बच गया। प्रार्थिक जानकारी के अनुसार दोनों दोस्त गुरुवार रात किसी कार्य से निकले थे।

रात करीब 2:40 बजे दादी का फाटक से मुरलीपुरा की ओर जाते समय केडिया चौराहे के पास वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह रैलिंग से जा टकराया। सूचना पर मुरलीपुरा थाना पुलिस और दुर्घटना थाना पश्चिम की टीम मौके पर पहुंची।

किरोड़ीलाल को हैसियत के अनुरूप पद नहीं मिला : रामकेश मीणा

सदन में उपनेता प्रतिपक्ष ने मंत्री किरोड़ीलाल की तारीफ में कसीदे गढ़े

जयपुर (विसं)। कांग्रेस विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने विधानसभा में डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की तारीफ करते हुए कई टिप्पणियां कीं, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। जिस पर सभापति ने आपत्तिजनक टिप्पणी को कार्यवाही से निकालने के निर्देश दिए। रामकेश मीणा ने अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कहा कि, डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा के लिए काफी काम किया, लेकिन उन्हें उनकी हैसियत के अनुरूप पद नहीं मिला। उन्हें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या गृहमंत्री बनाया जाना चाहिए था।

इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने तंज कसते हुए कहा कि कहीं डॉ. किरोड़ी गंगापुर से चुनाव न लड़ लें, इसलिए उनकी तारीफ की जा रही है। जवाब में रामकेश मीणा ने कहा कि डॉ. किरोड़ी उनके समाज के बड़े नेता हैं और यदि वे गंगापुर से चुनाव लड़ते हैं तो वे स्वयं सीट खाली करने को तैयार हैं। रामकेश मीणा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में भाजपा को खड़ा करने में डॉ. किरोड़ीलाल की बड़ी भूमिका रही है और उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पार्टी को उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

■ **मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने चुटकी लेते हुए कहा कि “कहीं डॉ. किरोड़ी गंगापुर से चुनाव न लड़ लें, इसलिए उनकी तारीफ की जा रही है।” जिसके जवाब में रामकेश मीणा ने कहा कि डॉ. किरोड़ी उनके समाज के बड़े नेता हैं और यदि वे गंगापुर से चुनाव लड़ते हैं तो वे स्वयं सीट खाली करने को तैयार हैं।”**

रामकेश ने कहा कि भाजपा पर जब भी कोई संकट आया तो इस बीजेपी को संकट से निकलने का काम किसी ने किया तो उसका नाम डॉ. किरोड़ी लाल मीणा है। ईआरसीपी को लेकर ढूंगरी बांध का मामला चल रहा है। जहां आंदोलन में लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। बीजेपी का एक व्याक्ति ढूंगरी बांध आंदोलनकारियों के

बीच जाकर अपनी बात कह दे, तो मान लूंगा। आप किरोड़ीलाल मीणा को भेजेंगे, वहां बैठने के लिए कहेंगे। लेकिन जब अधिकार लेने के बात आती है तो उन्हें आखिरी पंक्ति में बैठा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल लाल मामूलू व्यक्ति नहीं है, क्या समझ रहे हो भाजपा की ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगा तो वह किरोड़ीलाल मीणा है। आपने उनकी सारी शक्तियां छीन ली।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम ने आपत्ति जताते हुए कहा कि किरोड़ीलाल को कौन सी शक्ति नहीं दी, यह कौन सी डिमांड है? जोरेश्वर गंघे ने कहा दासा में उपचुनाव हुए तब भूल क्यों गए थे, किरोड़ी को क्यों हारे ? बहस के दौरान हुई तीखी टिप्पणियों से सदन का माहौल गरमा गया, हालांकि बाद में सभापति ने कार्यवाही से बाहर निकालने के निर्देश दिए। कांग्रेस विधायक अश्रण कुमार ने कहा कि सदन में जमाना कितना भी डिजिटल हो जाए लेकिन रोटी गूलल से डाउनलोड नहीं हो सकती। किसानों के ऋण वितरण समय पर होने चाहिए। ऋण माफ कर किसानों को परजीवी मत बनाओ। इसका स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए।

सीवरेज प्लांट्स पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट

यूडीएच मंत्री खर्ा ने अपने जवाब में इन प्रोजेक्ट्स की देरी के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया था

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान विधानसभा में प्रदेश में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अधूरे कार्यों को लेकर पूछे गए सवाल पर हंगामा हो गया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्ा के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने प्रश्न उठाया कि शहरों में व्यापक खुदाई की गई है, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के काम अब भी अधूरे हैं। उन्होंने पूछा कि इन ट्रिटियों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जलाई और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए स्पीकर ने

■ **मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई और हंगामा शुरू कर दिया, स्थिति को देखते हुए स्पीकर ने अगला प्रश्न ले लिया। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए।**

परियोजनाओं में ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की शर्तों का पालन नहीं हुआ। सीवरेज पाइपलाइन डालते समय इनलेट और आउटलेट का स्तर सही नहीं रखा गया, जिससे तकनीकी दिक्कतें आईं। उन्होंने कहा कि इन ट्रिटियों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जलाई और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए स्पीकर ने

अगला प्रश्न ले लिया। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए।संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के रविये की निंदा करते हुए कहा कि अनुकूल जवाब नहीं मिलने पर वॉकआउट करना उचित नहीं है। वहीं बसपा विधायक मनोज न्यांगली ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि हंगामे और वॉकआउट से अन्य सदस्यों का समय प्रभावित होता है।

